www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया...
3 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता...
4 मेधा राणा ने बताया कैसा रहा बॉर्डर-2 की...

वर्षः 10 | अंकः 102 | दिल्ली, बुधवार, 4 फरवरी 2026 | पृष्ठ संख्याः 4 | मूल्यः 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

कागज उछालने पर कांग्रेस के 7 समेत 8 सांसद पूरे बजट सत्र से निलंबित

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सदन की कुर्सी पर कागज फेंकने के आरोप में आठ लोकसभा सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस और प्रशांत पाडोले शामिल हैं। इनमें से सात सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं, जबकि वेंकटेशन सीपीएम से हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरदीप सिंह औजला,हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए।

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1,237 लाभार्थियों को सहायक उपकरण किए वितरित

अशोकनगर/भोपाल (एजेन्सी)। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिले के मरूप गाँव में आयोजित भव्य दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सहायक उपकरण वितरण शिविर में संवेदना और सम्मान के संकल्प को साकार किया। इस अवसर पर उन्होंने 1237 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आधुनिक सहायक उपकरण वितरित करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल उपकरण वितरण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सशक्त कदम है। सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल में सेवा सिंधिया परिवार के लिए शासन का विषय नहीं, बल्कि पीढ़ियों से निभाया जा रहा एक पवित्र कर्तव्य रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अशोकनगर मे 1456, गुना में 1745 और शिवपुरी में 5250 सहित कुल पूरे संसदीय क्षेत्र में 8,240 दिव्यांगजनों तक सेवा पहुँचाने का लक्ष्य किसी आँकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 8,240 परिवारों की आशा, गरिमा और भविष्य से जुड़ा संकल्प है।

राष्ट्रपति ने फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया

भारत की ज्ञान की समृद्ध परंपरा है, हमारे शास्त्र और पांडुलिपियां ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं-राष्ट्रपति

संजना भारती/पीआईबी

ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया। उन्होंने इसके नए सभागार का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान वे उनकी कालजयी कहानी 'रेवती' से अत्यंत प्रभावित थीं। यह प्रभाव आज भी अमिट है। 19वीं शताब्दी में एक लड़की का शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प उनकी हिम्मत का अमिट प्रमाण है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दूरस्थ जनजातीय गांव में पढ़ाई की और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर भुवनेश्वर गईं, जहां उन्होंने अपनी हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी की। इस प्रकार, फकीर मोहन जी उनके लिए प्रेरणास्त्रोत रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि फकीर मोहन जी को अपनी मातृभाषा से गहरा प्रेम था। उन्होंने लिखा था, "मेरी मातृभाषा मेरे लिए सर्वोपरि है।" उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ अपने परिवेश, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। वे अपनी सभ्यता के मूल्यों और जीवनशैली से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया

कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मातृभाषा के महत्व पर बल देती है और विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए मार्गदर्शन करती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की ज्ञान की समृद्ध परंपरा है। हमारे शास्त्र और पांडुलिपियां ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं। कविता और साहित्य के अलावा, वे विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में भी ज्ञान का स्त्रोत हैं। युवा छात्र इस प्राचीन ज्ञान परंपरा में शोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत को समझकर और वर्तमान को आत्मसात करके छात्र अपना और देश का भविष्य संवार सकते हैं।

राष्ट्रपति ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और कहा कि ज्ञान, लगन और प्रतिबद्धता के बल पर वे समाज में सम्मान और पहचान हासिल कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे जहाँ भी जाएँ और जो भी करें, हर प्रयास में सफलता की कुंजी समर्पण है। उन्होंने कहा कि सफल जीवन और सार्थक जीवन एक समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सफल जीवन अच्छा है, लेकिन जीवन को सार्थक बनाना उससे भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे विकास की राह में पीछे रह गए लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि समाज का विकास सभी के विकास में निहित है।

राष्ट्रपति ने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की कि फकीर मोहन विश्वविद्यालय अकादमिक अध्ययन के साथ-साथ अनुसंधान और लोकसंपर्क कार्यक्रमों को भी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि बालासोर-भद्रक क्षेत्र धान, पान और मछली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इन क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के 'बैक टू स्कूल', 'कमाओ और सीखो', 'हर ०?यक्ति एक दूसरे को सिखाए' जैसे कार्यक्रम और पर्यावरण जागरूकता एवं समुद्र तट सफाई कार्यक्रम प्रशंसनीय हैं। बालासोर और भद्रक के समुद्र तटों पर नीले केकड़े बहुतायत में पाए जाते हैं, ऐसे में नीले केकड़ों या हॉर्सशू केकड़ों पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय की दूरदर्शिता को दशार्ती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की वृद्धि, सुरक्षा और तकनीकी विकास से देश की प्रगति में तेजी आएगी। इस क्षेत्र में देश के सभी विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समावेशी विकास, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की विश्वविद्यालयों की विशेष जिम्मेदारी है।

विरासत को मिलेगा संरक्षण, पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी पुरानी दिल्लीः सीएम रेखा गुप्ता

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी के ऐतिहासिक क्षेत्र पुरानी दिल्ली के विकास को अब नई दिशा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में लोकनिवास से आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। एसआरडीसी के माध्यम से पुरानी दिल्ली को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

अध्यक्ष पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पुरानी दिल्ली यानी वॉल्ड सिटी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्जीवित करना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। शाहजहानाबाद केवल इलाका नहीं, बल्कि दिल्ली की समृद्ध विरासत और इतिहास की पहचान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में फैले बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और क्षेत्र की सुंदरता में भी

सुधार होगा। साथ ही, बाजारों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा और मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी दिल्ली ऐतिहासिक रिहायशी क्षेत्र है, जहां हर गली में इतिहास और विरासत की झलक मिलती है। सरकार का उद्देश्य इस विरासत को सहेजते हुए क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। हवेलियों के संरक्षण के साथ-साथ कटरों और कूंचों को भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआरडीसी ने पूर्व में भी पुरानी दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार की थीं। इनमें चांदनी चौक का पुनर्विकास, जामा मस्जिद क्षेत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक की सड़क का सौंदर्यीकरण शामिल है। इन सभी योजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि पुरानी दिल्ली को बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में पुरानी दिल्ली अपेक्षित विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही। अब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों का निर्माण बिना किसी बाधा के हो, गलियों को दुरुस्त किया जाए, जर्जर सीवर व्यवस्था को सुधारा जाए और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए स्पष्ट ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए। पुरानी दिल्ली को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 1 मई 2008 को दिल्ली सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन संस्था के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देना है।

स्पेशल ओलंपिक केवल खेल नहीं, आत्मविश्वास और नेतृत्व का आंदोलन हैः मुख्यमंत्री सैनी

अवसर और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता हैः सीएम

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्त्रोत और रोल मॉडल बनते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

कानून के राज में ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी बनी यूपी की पहचानः सीएम योगी

एआई, मेड-टेक, हेल्थ-टेक और क्लिनिकल रिसर्च का नया केंद्र बनेगा यूपी

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को होटल ताज में आयोजित वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए भरोसे की गारंटी बन चुका है। प्रदेश सरकार हर निवेशक को ट्रिपल-एस यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की पूर्ण गारंटी देती है और उत्तर प्रदेश आज ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी का रोल मॉडल बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ पूरी मजबूती से लागू है। कानून से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं है। यदि कोई कानून को आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो कानून अपने दायरे में लाकर उसे उसकी ही भाषा में जवाब देता है। यह नया उत्तर प्रदेश है, जहां व्यवस्था कमजोर नहीं, बल्कि निर्णायक है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश असुरक्षा, अराजकता और अविश्वास का पर्याय बन चुका था। वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 900 से अधिक दंगे हुए। शायद ही कोई शहर रहा हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो। उद्योग, व्यापार और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को गुंडा टैक्स देना पड़ता था। सुरक्षा के अभाव में पहले से स्थापित उद्योग भी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर थे, युवा वर्ग पलायन कर रहा था। जिस धरती पर बचपन बीता हो, उसे छोड़ना किसी के लिए भी पीड़ादायक होता है, लेकिन असुरक्षा के चलते मजबूरी थी। यह केवल किसी एक उद्यमी की पीड़ा नहीं थी, बल्कि हर व्यापारी, हर निवेशक और हर नागरिक की व्यथा थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह दायित्व सौंपा, तो सबसे बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करना था। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमने स्पष्ट कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। आज इसका परिणाम सबके सामने है। बड़े पर्व-त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। कहीं दंगे नहीं, कहीं फिरौती नहीं, कहीं गुंडा टैक्स नहीं। उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का वातावरण है और यही निवेश की सबसे मजबूत नींव है।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज डी-रेगुलेशन रैंकिंग में देश में नंबर वन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर बन चुका है। डी-क्रिमिनलाइजेशन के तहत 13 राज्य अधिनियमों में मौजूद आपराधिक प्रावधानों को समाप्त किया गया, ताकि उद्योग बिना भय और बाधा के कार्य कर सकें। एमएसएमई सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को 1000 दिनों तक निरीक्षण से छूट दी गई है।

मतदाता सूची का संशोधन केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है-ममता

पश्चिम बंगाल (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इससे एक दिन पहले उन्होंने चुनाव वाले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची का संशोधन केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है और यह प्रक्रिया बिना उचित तैयारी और प्रशिक्षण के जल्दबाजी में की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव की पूर्व संध्या पर ऐसा क्यों? क्योंकि फरवरी में, इसी महीने, वे (चुनाव आयोग) अधिसूचना जारी कर सकते हैं। तो क्या बिना योजना, बिना मानचित्रण, बिना उचित प्रशिक्षण और बिना उचित बुनियादी ढांचे के दो-तीन महीनों में एसआईआर को पूरा करना संभव है? दरअसल, देखिए, चार चुनाव वाले राज्य हैंः बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। वे इसे केवल तीन राज्यों में, यानी विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में ही कर रहे हैं-असम में नहीं, क्योंकि यह दो इंजन वाला राज्य है।

यमुना हादसे में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ता कुलदीप नैनवाल की धर्मपत्नी को मिली नौकरी

मंत्री कपिल मिश्रा के प्रयासों से पीड़ित परिवार को मिली मदद

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी में हुए दुखद हादसे में जान गंवाने वाले स्वर्गीय श्री कुलदीप नैनवाल की धर्मपत्नी दीपा नैनवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा नौकरी प्रदान की गई। यह नियुक्ति पहले लिए गए निर्णय के अनुरूप आज संपन्न हुई, जिससे पीड़ित परिवार को स्थायी आजीविका और भविष्य का संबल मिल सके।

यह कार्य विधि एवं न्याय मंत्री तथा करावल नगर के विधायक श्री कपिल मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार संकट की घड़ी में केवल आश्वासन नहीं देती, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस निर्णय लेकर पीड़ित परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करती है।

मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा, भाजपा के हर कार्यकर्ता के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और किसी भी मुसीबत में एक परिवार की तरह साथ देंगे। यह नियुक्ति उसी सोच का परिणाम है, जिसमें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दोनों शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दिल्ली सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा बेटी की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की घोषणा भी की गई थी। आज दी गई नौकरी उसी क्रम में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है।

नौकरी मिलने पर दीपा नैनवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री श्री कपिल मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय उनके परिवार के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से हिंदुजा ग्रुप ने पंजाब में निवेश में गहरी रुचि दिखाई, युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

मुंबई। पंजाब को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश में और तेजी आई है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विश्व प्रसिद्ध कंपनी हिंदुजा ग्रुप के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद कंपनी ने राज्य में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पंजाब को एक स्थिर, भविष्य के लिए तैयार और व्यवसाय-अनुकूल स्थान के रूप में पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र, नीतिगत सुधारों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को उजागर किया, जिसके कारण मार्च 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इलेक्ट्रिक गतिशीलता से लेकर डिजिटल सेवाओं तक के क्षेत्रों के विस्तार का स्पष्ट रोडमैप तैयार करने में मदद मिली है।

बैठक के दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, निवेश के दृष्टिकोण से पंजाब देश का सबसे पसंदीदा राज्य है क्योंकि यहां बुनियादी ढांचे की बेहतर सुविधाएं, अतिरिक्त बिजली, कुशल मानव संसाधन, शानदार सड़क, रेल और हवाई संपर्क, बेहतर दूरसंचार नेटवर्क और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन, वित्तीय और डिजिटल सेवाएं, डिजिटल तबदीली और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक प्रभाव, औद्योगिक और रियल एस्टेट सहयोग, रणनीतिक प्राप्तियां और निवेश जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अथाह संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, पंजाब के पास लचीलापन, उद्यमी मानसिकता और समृद्ध विरासत है और हिंदुजा ग्रुप इसका लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को भारत का अन्नदाता होने का सौभाग्य प्राप्त है और देश के अनाज भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां पंजाब ने परंपरागत रूप से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं राज्य का औद्योगिक क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा, आज पंजाब एक औद्योगिक पावरहाउस है, जो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के औद्योगिक विकास ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है और दुनिया भर के निवेशक राज्य की क्षमताओं को मान्यता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 5.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने की संभावना है। राज्य औद्योगिक विकास और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।

विश्वस्तरीय निगमों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डैनोन जैसी कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में व्यवसायों के विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए उद्योग-अनुकूल माहौल का लाभ उठा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की वैश्विक पहुंच जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों द्वारा राज्य में निवेश की रुचि से स्पष्ट होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की विकास गाथा अभी शुरूआती दौर में है। भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब अब न केवल भारतीय निवेशकों के लिए बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थान बन गया है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में, राज्य सरकार ने जापान और कोरिया गणराज्य में उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां की हैं, जिससे पंजाब की वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, इन गतिविधियों ने उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और खेल विज्ञान में सहयोग के लिए नए रास्ते खोले हैं।

सम्पादकीय

सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जमीन के नीचे रेल दौड़ाने की तैयारी!

पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी गलियारा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। यह धरती की वही पतली पट्टी है जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई करीब पच्चीस कोस से भी कम मानी जाती है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर भूटान और पास ही बांग्लादेश की सीमा है। यही रास्ता पूर्वोत्तर के आठों राज्यों के लिए जीवन रेखा है। सेना की आवाजाही हो, अनाज और ईंधन की आपूर्ति हो या व्यापार, सब कुछ काफी हद तक इसी राह से गुजरता है। केंद्र सरकार ने अब इस गलियारे की सुरक्षा और मजबूती के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि करीब चालीस कोस लंबे हिस्से में भूमिगत रेल पटरियां बिछाने की योजना बनाई गई है। तीन मील हाट से रंगापानी के बीच यह भूमिगत मार्ग बनेगा। साथ ही पूरे मार्ग को चार पटरियों वाला बनाने का प्रस्ताव भी वार्षिक लेखा योजना में रखा गया है ताकि यातायात की क्षमता कई गुना बढ़ सके। हम आपको बता दें कि हाल के समय में इस गलियारे को लेकर कई तरह की गीदड़ भभकियां सामने आईं थीं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ समूहों ने चिकन नेक को दबाने जैसी बातें कही थीं। कुछ बयान ऐसे भी आये जिनमें इस इलाके को ग्रेटर बांग्लादेश की कल्पना से जोड़ा गया। ढाका की चीन से बढ़ती नजदीकी ने भी चिंता बढ़ाई। वर्ष 2017 में डोकलाम टकराव के समय भी सैन्य योजनाकारों ने सिलीगुडी हिस्से की कमजोरी पर ध्यान दिलाया था। साफ था कि यदि यहां बाधा आई तो पूर्वोत्तर लगभग कट सकता है। इसी पृष्ठभूमि में भूमिगत रेल को संकट के समय भी संपर्क बनाए रखने की योजना के रूप में देखा जा रहा है। भूमिगत मार्ग पर सीधा प्रहार करना कठिन होगा। इससे सैनिक साजो सामान और आम जन जीवन की आपूर्ति निरंतर बनी रह सकती है। यदि चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके में भूमिगत रेल मार्ग बनता है तो यह कौशल, साहस और दूरदर्शिता का भी प्रदर्शन होगा। भारत पहले ही जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कर अपनी प्रतिभा दिखा चुका है। पहाड़ चीरकर और पहाड़ों के ऊपर पुल खड़ा करने वाले यही हाथ जमीन के भीतर भी सुरक्षित मार्ग बना सकते हैं। वैसे भी कठिन भौगोलिक हालात को मात देना भारतीय इंजीनियरों की पहचान बन चुकी है, इसलिए चिकन नेक में भूमिगत रेल केवल सुरक्षा कदम नहीं, बल्कि देश की तकनीकी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक भी होगी। देखा जाये तो यह गलियारा केवल भौगोलिक पट्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की धुरी है। इसलिए इसकी सुरक्षा पर किसी तरह की ढिलाई नहीं हो सकती। भूमिगत रेल, चार पटरी विस्तार और कड़ी निगरानी को उसी दिशा में उठे कदम के रूप में देखा जा रहा है। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह इलाका चार देशों के बीच घिरा है। सीमा पार से होने वाली हर हलचल यहां असर डालती है। चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और खुले सीमा प्रबंध वाले इलाकों की जटिलता, सब मिलकर इस पट्टी को संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे में भूमिगत रेल केवल ईंट पत्थर का काम नहीं, बल्कि संकट काल में जीवन रेखा को जिंदा रखने का उपाय है। युद्ध या बड़े तनाव की स्थिति में खुली पटरियां आसान निशाना बन सकती हैं, पर जमीन के भीतर चलने वाली रेल को रोकना कठिन होगा। इसका आर्थिक पक्ष भी कम अहम नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति, कृषि उपज और सीमा पार व्यापार की अपार संभावना रखता है। यदि संपर्क मजबूत होगा तो उद्योग, पर्यटन और व्यापार को बल मिलेगा। चार पटरी मार्ग का अर्थ है तेज आवागमन, कम बाधा और ज्यादा माल ढुलाई। इससे लागत घटेगी और बाजार बढ़ेंगे, जो इलाका कभी दूर माना जाता था वह अवसर का द्वार बन सकता है।

जयंती

एम. ए. अय्यंगार

जन्म: 4 फरवरी, 1891, मृत्यु: 19 मार्च, 1978, भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के आकस्मिक निधन से पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करके मदभूषी अनन्तशयनम् अय्यंगार ने स्वतंत्रता की उपलब्धियों तथा नव गणतंत्र में स्वस्थ संसदीय संस्कृति को विकसित करने के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने आपको सर्वोपयुक्त सिद्ध किया। अय्यंगार ने छह दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में, एक वकील, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उत्कृष्ट सांसद तथा लोक सभा अध्यक्ष और एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में, जीवन में जिस भी कार्यक्षेत्र को चुना उसमें अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे।

पुण्यतिथि

सत्येंद्रनाथ बोस

जन्म: 1 जनवरी, 1894 कोलकाता; मृत्यु:4 फरवरी, 1974 कोलकाता, प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं- बोसॉन और फर्मियान। इनमें से बोसॉन सत्येन्द्र नाथ बोस के नाम पर ही है।

कल मिलेंगे

सुरेश की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए...
सुरेश ने नर्स से बोला-बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना,
नर्स-मतलब
सुरेश-लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है...
इत्तेफाक से सुरेश की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की...
नर्स कन्फूयजन में बाहर आकर बोली बधाई हो सलाद हुआ है...

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी। **मुद्रक**-देवानंद राय।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस वर्ष का बजट

भारत में उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में रेल्वे की मुख्य भूमिका रहती है। भारत में इन उत्पादों की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 नए हाई स्पीड रेल कोरिडोर बनाए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। यह कोरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे

-प्रहलाद सबनानी

दिनांक 1 फरवरी 2026 को, रविवार के दिन, भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भारतीय संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में की गई घोषणाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर घटित हो रही उथल पुथल से भारत को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई दिखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपने द्वितीय कार्यकाल में वर्ष 2025 के दौरान पूरे वर्षभर लगातार कई देशों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की घोषणाएं की जाती रहीं एवं इसके विरोध स्वरूप कुछ देशों ने अमरीका से इन देशों को होने वाले निर्यात पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने की घोषणाएं की जाती रहीं। चीन ने तो प्रतिशोध में अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थों की आपूर्ति ही रोक दी थी। हालांकि इसके पूर्व अमेरिका ने भी चीन को सेमीकंडक्टर एवं चिप्स की आपूर्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर, कुछ देश तो आपस में विभिन्न वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को रोकने के प्रयत्न करते रहे। इन सभी घोषणाओं से वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में माहौल विपरीत रूप से प्रभावित होता रहा। ट्रम्प प्रशासन ने भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जो अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में संभवतः आज अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है।

इस वित्तीय वर्ष के बजट में तीन कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया है। (1) विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक तेज किया जाय ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल से बचाया जा सके; (2) भारतीय युवाओं में कौशल का विकास करना ताकि तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें; (3) देश में समावेशी विकास हो सके एवं भारत के संसाधनों का उपयोग समस्त नागरिकों की भलाई में किया जा सके और कोई भी नागरिक, नगर एवं राज्य आर्थिक विकास की धारा से बाहर नहीं रहे। वैश्विक स्तर पर उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रही। परंतु, भारत की विकास दर की इस गति को आगामी वर्षों में भी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। भारत आज दुर्लभ खनिज पदार्थों तथा सेमीकंडक्टर एवं चिप्स का भारी मात्रा आयात करता है। चिप्स को तो आज के उत्पादों के निर्माण में तेल की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। इन दोनों पदार्थों पर चीन एवं अमेरिका का लगभग पूर्णतः एकाधिकार है। भारत अपने आप को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, इस दृष्टि से बजट में भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओड़िसा, केरल, तमिलनाडु एवं आन्ध्रप्रदेश स्थित खदानों में से कच्चे माल को निकालकर इसे संसाधित करते हुए भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में उक्त चारों राज्यों में एक कोरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार, भारत में ही सेमीकंडक्टर एवं चिप्स के निर्माण हेतु विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है एवं इस हेतु 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, इसके लिए बजट में सेमीकंडकर मिशन 2.0 को लागू करने की भी घोषणा की गई है। इससे कम्पनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों को स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इन समझौतों में 27 विकसित देशों के समूह, यूरोपीयन यूनियन से किया गया मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। इसे मदर आफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि यह समझौता 28 देशों (27+1) के बीच एक साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है। इन मुक्त व्यापार समझौतों से भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग, समुद्रीय पदार्थ उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग एवं जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, आदि को सबसे अधिक लाभ होने जा रहा है। इन उद्योगों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम भारी मात्रा में कार्यरत हैं। भारत में उक्त वर्णित पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को रियायतें देने का प्रयास किया गया है ताकि उक्त वर्णित उत्पादों की मांग में होने वाली वृद्धि को पूर्ण किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड भी बनाया गया है। टेक्स्टायल उद्योग को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत में निर्मित वस्त्र एवं परिधानों को विश्व के पटल पर रखा जा सके। साथ ही, बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था, बायोफार्मा शक्ति के रूप में, इस बजट में की गई है। इससे भारतीय दवा उद्योग को विश्व के मानचित्र पर और आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में विकसित आधारभूत संरचना की अहम भूमिका रहती है। इस बजट के माध्यम से भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों में भारी भरकम वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्चों के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी, इसे वर्ष 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014-15 के बजट में पूंजीगत खर्चों के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। पिछले 13 वर्षों में पूंजीगत खर्चों में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। पूंजीगत खर्चों में वृद्धि से कई क्षेत्रों में सरकारी निवेश भी बढ़ता है एवं इससे अंततः रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। बल्कि, अब तो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ाना होगा। क्योंकि, सरकार के पूंजीगत खर्चों में अतुलनीय वृद्धि से देश में ही विभिन्न उत्पादों के निर्माण में तेज गति से वृद्धि होगी और वर्तमान विनिर्माण इकाईयों की उत्पादन क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से ऊपर निकल जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है, इससे नई उत्पादन इकाईयों को स्थापित करना आवश्यक होगा। अतः भारत में अब निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा, इसमें विदेशी निवेश भी शामिल है।

भारत में उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में रेल्वे की मुख्य भूमिका रहती है। भारत में इन उत्पादों की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 नए हाई स्पीड रेल कोरिडोर बनाए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। यह कोरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। यह क्षेत्र विकास के नए केंद्र बन जाएंगे।

भारत को विश्व में लाजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया जा रहा है ताकि भारत में ही कंटेनर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में मेडिकल टुरिजम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हब बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं राज्यों को भी साथ में लिया जाएगा। इससे भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी एवं अन्य देशों के नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत की ओर आकर्षित होंगे। इसी प्रकार, भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बौद्ध सर्किट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे अन्य देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में धार्मिक पर्यटन हेतु आकर्षित हो सकेंगे। भारत को पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि भारत में समस्त धर्मों का आदर किया जाता है।

पूरे विश्व में ऐनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने एवं इस क्षेत्र को भारत में ही बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का निर्णय इस बजट में किया गया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस हेतु भारत में ही विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इस क्षेत्र में शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

आयकर की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। जबकि आयकर के नियमों को सरल बनाया गया है। आय कर की नई योजना के अंतर्गत अब 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर लगाया जाएगा। आयकर रिटर्न फाइल करने हेतु समय सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार, इस संदर्भ में आयकर नियमों को सरल बनाया जा रहा है

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट की कुछ मुख्य विशेषताओं में वित्तीय अनुशासन का अनुपालन किया जाना भी शामिल है। बजटीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के अंदर रखने का प्रयास सफल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल हुई है। जबकि, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी आज बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजटीय घाटे को कम करते हुए इसे 4.3 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पूंजीगत खर्चों में 1.1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि भी प्रस्तावित है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

विकासशील देशों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम करना होगा

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नारे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि केनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डब्ल्यूईएफ में अपने भाषण में कहा, 'अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था (इंटरनेशनल ऑर्डर) टूट गयी है'

-डॉ. अरुण मित्रा

वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की 56वीं सालाना बैठक, जो 19-23 जनवरी 2026 को दावोस में 'ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग' थीम के तहत हुई, वह वैश्विक व्यापार संबंधों में भारी तनाव के माहौल में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदमों ने देशों के बीच सहयोग के बने-बनाए ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यह आम तौर पर महसूस किया गया कि वैश्विक लड़ाई से बचने के लिए अलग-अलग देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना जरूरी है। इसी संदर्भ में, बातचीत और अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए एक साझे मंच के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों-संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ (अब रूस), फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन-को दी गई ज्यादा शक्ति के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने शांति और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, नाभिकीय हथियारों के खतरों को जोरदार ढंग से सामने लाने, बच्चों की भलाई,सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन जुटाने और इंसानों की बनाई और कुदरती, दोनों तरह की मुश्किलों से निपटने में अहम भूमिका निभायी है। इसने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने में भी मदद की है।

1964 में बनी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड) का मकसद विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास से फायदा पहुंचाने में मदद करना और उन्हें बराबरी की शर्तों पर विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना था। अंकटाड नीति विश्लेषण देकर, आम सहमति बनाने में मदद करके और खासकर कम विकसित देशों (एलडीसी) को तकनीकी मदद देकर व्यापार और विकास के लिए एक केन्द्रीय बिंदु के तौर पर काम करता है।

इसी तरह, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट), जो 1947 की एक बहुपक्षीय संधि थी, ने टैरिफ, कोटा और सब्सिडी में कमी करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाकर युद्ध के बाद आर्थिक सेहत में सुधार को तेज करने की कोशिश की। 1995 में, गैटकी जगह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने ले ली। हालांकि डब्ल्यूटीओ की विकसित देशों के पक्ष में होने के लिए बहुत आलोचना हुई है, लेकिन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) और ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स (ट्रिम्स) जैसे समझौतों के कई प्रावधानों का इस्तेमाल विकासशील देश अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि इन व्यवस्थाओं ने कम से कम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नियम-आधारित प्रणाली दी।

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नारे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि केनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डब्ल्यूईएफ में अपने भाषण में कहा, 'अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था (इंटरनेशनल ऑर्डर) टूट गयी है।' उन्होंने मध्यम आय वाले देशों से एकजुट होने की अपील की। यह ट्रंप की नीति की अप्रत्यक्ष आलोचना थी और उसका विरोध था। ट्रंप ने अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग बातचीत करके अपना टैरिफ एजेंडा लागू करने की कोशिश की, जिससे बहुपक्षवाद कमजोर हुआ। उनके इरादे तब और साफ हो गए जब उन्होंने पनामा कैनाल और गल्फ ऑफ मेक्सिको पर नियंत्रण और यहां तक कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैश्विक तेल संसाधनों में अपनी दिलचस्पी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण ने दुनिया भर में राष्ट्रीय सम्प्रभुता के लिए सीधी चुनौती पेश की। इस प्रक्रिया में, ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक साथियों को भी कमजोर किया। कई यूरोपीय देशों ने पहले इराक और लीबिया में अमेरिकी सैन्य दखल का समर्थन किया था, सीरिया में बागी ताकतों का साथ दिया था, और ईरान में अमेरिका के नेतृत्व में सरकार बदलने की कोशिशों का समर्थन किया था। गाजा में नरसंहार के दौरान भी, उन्होंने हल्के-फुल्के एतराज के साथ इजराइल का साथ दिया था। पहले, वे पुराने सोवियत संघ से पैदा किए गए खतरे के जवाब में अमेरिका के साथ थे। लेकिन, जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती या खरीदकर कब्जा करने का प्लान बताया, तो इन देशों को अमेरिका के एकतरफा फैसले का असर महसूस होने लगा। नतीजतन, यूरोपियन यूनियन के देश, जिनमें से कुछ कभी औपनिवेशिक ताकतें थीं, अमेरिकी चुनौती का सामना करने के लिए दूसरे तरीके खोजने लगे। यह घटनाक्रम वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है।

इसी संदर्भ में, लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौता-जिस पर 2007 से बातचीत चल रही थी-27 जनवरी 2026 को पूरा हुआ। इस समझौते पर सावधानी से नजर रखनी होगी क्योंकि ईयू की बड़ी मांगें-जिसमें बौद्धिक सम्पदा, सरकारी खरीद, खेती और नियामक मानक भी शामिल हैं-भारत के विकास, औद्योगिक विकास, और जन कल्याण के लिए नीतिगत जगह को हमेशा के लिए रोकना चाहती हैं, जो भारत की आर्थिक सम्प्रभुता, रणनीतिगत स्वायत्तता और नागरिकों की भलाई का एक गलत उल्लंघन है। साथ ही, टैरिफ खत्म होने से बाजार में बाढ़ आ जाएगी। इससे विनिर्मित सामान की भी बाढ़ आ जाएगी, जिससे भारत में उद्योगीकरण में विलोम गति (डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन), बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान और सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) का विनाश होगा। इसके अलावा, ईयू की प्रस्तावित बौद्धिक सम्पदा प्रणाली भारत के जेनेरिक दवाओं के सेक्टर को पंगु बना देगा, जिससे जरूरी दवाएं महंगी हो जाएंगी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ धोखा होगा। भूमंडलीय वैश्विक राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और नए रूझान सामने आ रहे हैं। इस नाजुक मोड़ पर, वैश्विक दक्षिण के विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता के सम्मान, हथियारों की होड़ को खत्म करने और आपसी फायदे पर आधारित आर्थिक विकास की अपनी प्रणाली विकसित करना जरूरी है।

हाल के सालों में, कई विकासशील देश मदद के लिए तेजी से चीन की ओर मुड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहल एक सकारात्मक कदम है। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) जैसे प्लेटफॉर्म का उभरना भी उत्साहजनक है। आज की स्थिति में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक दक्षिण के सबसे गरीब देशों के हितों को नजरअंदाज न किया जाए। भारत सहित कई विकासशील देशों में, आर्थिक विकास का फायदा समाज के कुलीन वर्गों को असमान रूप से मिला है। इसलिए, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नैम) जैसे संगठनों को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए, और सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग मंचों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियां समानता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए।

भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में नई गर्माहट: एस जयशंकर की स्कॉट बेसेंट और मार्को रुबियो से अहम मुलाकात

(एजेन्सी)।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की वर्तमान अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरूआत के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग आगे बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मिलकर खुशी हुई। भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई।

वहीं बेसेंट ने एक पोस्ट में कहा कि उन्हें जयशंकर से मुलाकात करके अच्छा लगा। उन्होंने कहा, इस बातचीत के दौरान हमने आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के महत्व के साथ-साथ आपसी हित के अन्य राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की। जयशंकर दो से चार फरवरी तक अमेरिका की यात्रा पर हैं और बुधवार को विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर से बुलाई गई महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में वह हिस्सा लेंगे।

जयशंकर ने विदेश मंत्रालय में रुबियो के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की जहां दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति का स्वागत किया और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज एवं खनन पर द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने पर भी चर्चा की। जयशंकर की बेसेंट और रुबियो के साथ बैठक ट्रंप द्वारा ट्रुथ सोशल पर यह घोषणा करने के एक दिन बाद हुई कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं जिसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

जयशंकर ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मिलकर खुशी हुई। भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई।"

भारत-पाक तनाव के बीच महिला क्रिकेट पर असर नहीं, बैंकॉक में तय मुकाबला कायम

(एजेन्सी)।

भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर जारी विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका असर महिला क्रिकेट तक नहीं पहुंचा है। बता दें कि पाकिस्तान महिला ए टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत महिला ए टीम के खिलाफ खेलने की तैयारी में जुटी हुई है और अब तक किसी तरह के बहिष्कार के निर्देश सामने नहीं आए हैं।

मौजूद जानकारी के अनुसार, यह टूर्नामेंट 13 फरवरी से बैंकॉक में शुरू हो रहा है और भारत महिला ए तथा पाकिस्तान महिला ए के बीच मुकाबला 15 फरवरी को प्रस्तावित है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होनी थीं, जिसे लेकर पाकिस्तान सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी पुरुष टीम उस मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

गौरतलब है कि पुरुष मुकाबले को लेकर उठे सियासी फैसले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महिला ए टीम का स्क्वॉड जारी कर दिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि कम से कम महिला टीम के कार्यक्रम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पाकिस्तान महिला ए टीम को ग्रुप ए में भारत ए, यूएई और नेपाल के साथ रखा गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, राइजिंग स्टार्स एशिया कप की तैयारियां तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अभी इस पूरे मसले पर औपचारिक बैठक बुलाने को लेकर किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब तक आईसीसी की किसी आपात बैठक की घोषणा नहीं हुई है। गौरतलब है कि आईसीसी पहले ही यह कह चुकी है कि चयनात्मक भागीदारी जैसे फैसले वैश्विक टूर्नामेंट की निष्पक्षता और खेल भावना के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं। हालांकि पुरुष क्रिकेट में स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन महिला क्रिकेट में अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत-पाक मुकाबले को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा।

फिलहाल हालात यही बताते हैं कि राइजिंग स्टार्स एशिया कप में महिला ए स्तर पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने उतर सकती हैं और दोनों देशों के बीच महिला क्रिकेट को इस राजनीतिक खींचतान से अलग रखा गया है।

रिकॉर्ड ऊंचाई से धड़ाम गिरे सोना और चांदी के दाम

(एजेन्सी)।

पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दाम किसी झूले की तरह ऊपर-नीचे होते नजर आ रहे हैं। एक समय रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद इन कीमती धातुओं में अचानक तेज गिरावट आई, जिसने निवेशकों को चौंका दिया है। हालांकि मंगलवार को कीमतों में थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी वे अपने शिखर से काफी नीचे बनी हुई हैं।

बता दें कि बीते एक साल में सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बने रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक तनाव के दौर में इन धातुओं को सुरक्षित निवेश माना जाता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी को भी बाजार में अस्थिरता बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। उनके टैरिफ फैसले, फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर बयान और विदेश नीति से जुड़े अप्रत्याशित कदमों ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है।

गौरतलब है कि ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आई, जिससे सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने और चांदी की मांग और बढ़ गई। ट्रंप के शपथ ग्रहण से लेकर जनवरी 2026 के अंत तक सोने की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं, जबकि चांदी में करीब चार गुना तक की तेजी देखने को मिली है। मौजूद जानकारी के अनुसार, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह तेजी सिर्फ बाजार की अस्थिरता नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचे में भरोसे की कमी को भी दशार्ती है। लगातार ऊंची महंगाई, बढ़ता सार्वजनिक कर्ज और आर्थिक दबावों ने निवेशकों को पारंपरिक मुद्राओं से हटकर कीमती धातुओं की ओर मोड़ा है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों, खासकर चीन और तुर्किये, द्वारा सोने की लगातार खरीद भी मांग को सहारा दे रही है। ये देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

हालांकि यह तेजी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। बीते गुरुवार को सोना करीब 5,595 डॉलर प्रति औंस और चांदी लगभग 122 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, लेकिन शुक्रवार को दोनों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। सोने के दाम करीब 10 प्रतिशत और चांदी लगभग 28 प्रतिशत तक टूट गए हैं। सोमवार को भी गिरावट जारी रही, जबकि मंगलवार को आंशिक सुधार दर्ज किया गया है। कीमतों में इस गिरावट की वजहों को लेकर विशेषज्ञों में एकमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिकी फेड के लिए अपेक्षाकृत पारंपरिक चेहरे की नियुक्ति और ईरान से संभावित समझौते की उम्मीदों ने बाजार को थोड़ी स्थिरता का संकेत दिया है।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आहवान पर व्यापारियों ने प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू एवं प्रदेश मंत्री पवन जैन के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर जलूस की शक्ल में पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन कर विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 19 सूत्रीय मांग पत्र अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग चंद्रशेखर कुमार को उनके कार्यालय पर प्रेषित किया।

प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने से पूर्व विभाग में जमा की गई सिक्योरिटी राशि उपभोक्ताओं को वापस कराई जाए साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि समाप्त कर केवल उपभोग की गई विद्युत यूनिट के आधार पर ही बिल की गणना की जाए साथ ही प्रीपेड मीटर लगाए जाने से पूर्व मीटर की जाँच लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा कराई जाना अनिवार्य किया जाए तथा लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष मीटर की जाँच सुनिश्चित की जाए। मीटर की जाँच की जिम्मेदारी विक्रेता अर्थात विद्युत विभाग की निर्धारित की जाए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाते समय मीटर का मैनुअल एवं गारंटी कार्ड उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए

प्रदेश मंत्री पवन जैन ने कहा बिजली कटौती हेतु रोस्टर घोषित किया जाए तथा उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए। अघोषित बिजली कटौती को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रार्थनापत्र जमा करने पर रिसीविंग नहीं दी जाती है। निर्देशित किया जाए कि किसी भी प्रार्थनापत्र को प्राप्त करते समय अनिवार्य रूप से रिसीविंग दी जाए। जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने मांग की विद्युत आपूर्ति व बिल सुधार से संबंधित शिकायत दर्ज करते समय शिकायत पर्ची बनाई जाए, जिसकी एक प्रति उपभोक्ता को भी उपलब्ध कराई जाए मीटर लगाए जाते समय अथवा मीटर उतारते समय सीलिंग सर्टिफिकेट मौके पर नहीं दिया जाता 100 प्रतिशत मामलों में मौके पर ही सीलिंग सर्टिफिकेट दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जिला महामंत्री हाजी राशिद जी ने कहा कि मीटर बदले जाने के पश्चात उन्हें लैब जाँच के लिए भेजा जाता है, जिसके आधार पर उपभोक्ता पर विद्युत चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं सीलिंग सर्टिफिकेट न मिलने के कारण उपभोक्ता को मीटर जाँच की तिथि, समय व स्थान की जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे भ्रष्टाचार व उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है।

नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलों में पोर्टल पर दर्शाई गई राशि एवं वास्तविक बिल राशि में अंतर पाया जा रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। निर्देश दिए जाएँ कि पोर्टल व बिल में एक ही राशि दर्शाई जाए।

नगर महामंत्री संजय रस्तोगी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं तथा सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी दी जा रही है, परंतु नेट मीटरिंग वाले उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा की रीडिंग घटवाने के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर में सुधार कर बिलों को सही किया जाए तथा खपत से अधिक उत्पन्न ऊर्जा का भुगतान भी उपभोक्ता को कराया जाए।

जिला उपाध्यक्ष जावेद खान ने कहा कि मीटर विभाग द्वारा चेक मीटर लगाए जाते समय सीलिंग सर्टिफिकेट उपभोक्ता को नहीं दिया जाता, जिससे चेक मीटर लंबे समय तक लगे रह जाते हैं। निर्देश दिए जाएँ कि चेक मीटर लगाते व उतारते समय सीलिंग सर्टिफिकेट मौके पर दिया जाए तथा निर्धारित समय में चेक मीटर अवश्य उतारा जाए।

नगर उपाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा 25 से 30 वर्ष पुराने पी.डी. कनेक्शनों की आर.सी. जारी की जा रही है, जबकि अधिकांश मामलों में मीटर उतारने का सीलिंग प्रमाण पत्र एवं अस्थायी विच्छेदन की तिथि विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट रूप से मनमानी एवं अवैध वसूली का संकेत है, जिस पर रोक लगाया जाना आवश्यक है जिला उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लाम्बा ने कहा कि पी.डी. होने की स्थिति में अस्थायी विच्छेदन की तिथि से ही फाइनल बिल बनाया जाना चाहिए, किंतु मनमाने ढंग से अंतिम बिल बनाए जा रहे हैं।

डेयरी उत्पादों के परीक्षण मानकों पर करनाल में मंथन

भारतीय मानक ब्यूरो और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का संयुक्त आयोजन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक संस्था भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के सहयोग से संस्थान परिसर में डेयरी उत्पादों के लिए परीक्षण विधियों पर भारतीय मानक विषय पर एक दिवसीय विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और डेयरी उत्पाद अनुभागीय समिति के सदस्यों सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

मुख्य वक्ता राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने कहा कि भारतीय मानकों के निर्माण और संशोधन में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाजार में उपलब्ध डेयरी उत्पादों की विविधता को देखते हुए मजबूत वैज्ञानिक आधार और विश्वसनीय परीक्षण विधियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मानकों को वर्तमान समय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए निरंतर सहयोग आवश्यक है।

भारतीय मानक ब्यूरो के खाद्य एवं कृषि विभाग की प्रमुख श्रीमती सुनीति टोटेजा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों की जानकारी दी। तकनीकी सत्र में डॉ. भावना, वैज्ञानिक, भारतीय मानक ब्यूरो ने डेयरी उत्पादों के परीक्षण से संबंधित मौजूदा भारतीय मानकों का अवलोकन प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के उप महाप्रबंधक श्री आदित्य जैन ने अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्थाओं के साथ भारत की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक डेयरी मानकीकरण में देश की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता बताई। वहीं डॉ. राजीव चावला ने डेयरी एवं खाद्य उत्पादों की जांच में उभरती नई प्रवृत्तियों की जानकारी दी।

मानकों में सुधार के सुझाव-संस्थान के संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) डॉ. राजन शर्मा ने घी, माल्टेड दूध खाद्य पदार्थ, लैक्टोमीटर और प्रवासन परीक्षण विधियों से जुड़े मानकों में संशोधन के सुझाव रखे। विशेषज्ञ समूहों ने दूध, मक्खन, घी और क्रीम के विश्लेषण एवं संवेदी परीक्षण विधियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

सत्र के दौरान मौजूदा मानकों में सुधार, नए मानकों के विकास और नई परीक्षण विधियों के लिए आगे अनुसंधान की आवश्यकता को चिन्हित किया गया। कार्यक्रम का समापन डेयरी उत्पादों के परीक्षण मानकों को और अधिक मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हुआ।

चेयरमैन फातमा रजा ने 2 करोड़ 46 लाख से 25 सड़कों की दी बदायूं शहर को सौगात

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं। नगर पालिका अध्यक्ष फात्मा रजा के नेतृत्व में शहर में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। पालिका चेयरमैन फात्मा रजा ने बिना किसी भेदभाव के हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों को साथ लेकर शहर की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं।

पालिका प्रशासन द्वारा लगभग 2 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से 25 सीसी सड़कों, नालों, पुलिया और इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया जा रहा है। इन योजनाओं के पूरा होने पर शहर के कई वार्डों में आवागमन सुगम होगा।

चेयरमैन फात्मा रजा ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हर वार्ड में जरूरत के अनुसार सड़क, नाला और इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है, जिससे बदायूं शहर सुंदर और व्यवस्थित बने। उन्होने कहा कि ऊपरपारा छोटे-बड़े सरकार रोड द वैन्यू हॉल से सज्जाद के मकान तक सीसी सडक व नाली निर्माण कार्य को ग्यारय लाख 89 हजार, लालपुल में खुराना टायर वालो के पास बाबूराम मौर्य से झाऊ के मकान तक व लिंक गली में सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य में पांच लाख 55 हजार, रंगीन मस्जिद से नूरउद्दीन से अख्तर के होटल तक सीसी रोड मय नाली निर्माण में दस लाख 58 हजार, वार्ड संख्या 18 में जीतपाल से इन्दू सक्सेना से प्रमोद मौर्य तक एवं विश्वास गुप्ता से हरीश नेकपाल तक सीसी रोड मय नाली कार्य में ग्यारह लाख 53900, कबूलपुरा में निर्माण कार्य शाहिद के मकान से होली चौक तक सीसी कार्य में 11,15000 और डीएम आवास के पीछे दिनेश कुमार लोटन वकील साहब से होते हुए मनोज बिहारी से आगे की ओर सीसी कार्य में 11 लाख 62 हजार 899 रुपये होगा।

पालिकाध्यक्ष फात्मा रजा ने कहा कि रंगरेजान वाली गली में राकेश के मकान से जाहिद के मकान तक सीसी कार्य 613000, वार्ड एक में निर्माण कार्य एप्रोच रोड पुलिया लोटनपुरा इण्टरलांकिग से 626000, वार्ड संख्या दो कृष्णापुरी में डा०एके वर्मा हास्पिटल से काशीराम मौर्य के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य 598000, जालन्धरी सराय नाईयों वाली गली में इकबाल के मकान से तक उल्ला से होते हुए मुस्तफा के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य 808000 साथ ही नागरान में हीरालाल वर्मा के मकान से बिलाल भाई से होते हुए नूरी मस्जिद तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य 888000, वार्ड संख्या एक में अब्दुल हसन के मकान से फकरुद्दीन के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य 576000, नई सराय नई बस्ती में लईक के मकान से छोटे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क उच्चीकरण का निर्माण कार्य 551000 तथा संतोष सिंह तिराहे के पास लक्ष्मी बिहार कालोनी से अलापुर रोड से महावीर सिह चौहान के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य 1151000, ब्राहमपुर में अशोक माहेश्वरी से सत्यपाल भदोरिया तक सीसी रोड कार्य 611660, वार्ड संख्या चौबीस में नत्थू के मकान से प्रीतम की पुलिया तक सीसी रोड मय नाली 1593000, मोहल्ला ऊपरपारा नईबस्ती में इशरत भाई के मकान से अलाउद्दीन के मकान तक इण्टरलांकिग सड़क व नाली निर्माण कार्य 1125000, मोहल्ला वार्ड न्यू आदर्श कालोनी गुडविल वाली गली में आशीष सक्सेना के मकान से अशोक मनसा ब्यूटी पार्लर से होते हुए रूपेश चौबे के मकान तक तथा मन्दिर वाली गली में सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य 1668000, नगर पालिका के गांधी ग्राउण्ड में गेट का निर्माण कार्य 1500000, छोटी ज्यारत रोड गेट पर मदरसा की पुलिया तक आरसीसी कवर्ड नाला निर्माण कार्य 2012840, लालपुल में डा० शान्ती प्रकाश क्लीनिक के पास रैप सहित कवर्ड नाले का निर्माण कार्य पांच लाख 78 हजार 679, जोगीपुरा में शान्ति प्रेस गली से शेखावत बिल्डिग होते हुए छः सड़का मुख्य नाले तक आरसीसी कवर्ड नाला निर्माण कार्य दस लाख 39 हजार 530, जोगीपुरा में खैराती चौक से नानक इलेक्ट्रिकल्स तक आरसीसी कवर्ड नाला निर्माण कार्य दस लाख 65 हजार 886 और वार्ड संख्या वार्ड 28 में निर्माण आरसीसी नाला कार्य अफजल से नसीम तक बारह लाख 28 हजार, गोपीचौक चौराहे पर रैंप सहित कवर्ड नाले का निर्माण कार्य 7 लाख 42 हजार 919 रुपये का होगा।

सांसद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं। बदायूं जनपद की कर्मठ लगनशील जुझारू महिला संतोष कश्यप जिला अध्यक्ष महिला सभा ने अपने निजी निवास पर अपनी समस्त महिला कार्यकारिणी साथियों को बुलाकर केक काटकर एक दूसरे के लिए खिलाया और सभी साथियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में जन्मदिन मनाया। जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थिति रही रही संतोष कश्यप, माला शर्मा, बबीता कश्यप, जया सिंह, बिनीता कश्यप, शब्बू खान, आरती ठाकुर, राजरानी, सुमन कश्यप, रामबेटी, रानी ठाकुर, अंजुम, नाहिद, प्रेमवती शाक्य, कमलेश यादव, अरुण यादव, अंजलि कश्यप, बृजेशा, जाटव, मीना, ओमवती, रीना, रमोला रिंकी, श्रीवास्तव, लता देवी, इमा इजहार, कमलेश जाटव, मुन्नी देवी शाक्य, मीना, ममता चंचल शर्मा गीता जाटव पुष्पा शाक्य अनीता ठाकुर पार्वती शर्मा आदि।

करनाल के राजेश खन्ना ने राष्ट्रीय स्तर पर रचा इतिहास

दो स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को दिलाई ओवरऑल चैंपियनशिप

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। करनाल के होनहार एथलीट एवं भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त राजेश खन्ना ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान के अजमेर स्थित पटेल स्टेडियम में 30 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आयोजित 7वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को ओवरऑल चैंपियनशिप दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों से करीब 1520 पुरुष व महिला एथलीटों ने भाग लिया। 50 प्लस आयु वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए राजेश खन्ना ने 4×100 मीटर रिले दौड़ और 4×400 मीटर रिले दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते हरियाणा टीम ने प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की। यह उपलब्धि न केवल करनाल बल्कि पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है।

उल्लेखनीय है कि राजेश खन्ना भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में एल्डिको कंपनी, पानीपत में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। खेल के प्रति उनकी निरंतर मेहनत और अनुशासन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर राजेश खन्ना का चयन आगामी ओपन वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स 2026 के लिए भी किया गया है, जो 6 से 15 फरवरी 2026 तक अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित होंगे। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और जिलेवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को सौंपे पदोन्नति पत्र

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कानूनगो से नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को पदोन्नति पत्र सौंपे। यह पदोन्नतियां निर्धारित सेवा नियमों के तहत तथा सभी विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत की गई हैं।

पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के सेवा हितों की सुरक्षा और उनके बनते अधिकार समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये पदोन्नतियां प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर जन सेवाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं। स. हरदीप सिंह मुंडियां ने पदोन्नत नायब तहसीलदारों से ईमानदारी, समर्पण और ज़िम्मेदारी के साथ कर्तव्य निभाने की अपील करते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी भूमि एवं राजस्व मामलों में जनता के लिए पहला संपर्क बिंदु होते हैं।

प्रशासनिक सेवाओं पर उनके आचरण और कार्यशैली का जनता के विश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे और बिना किसी पक्षपात के जनता की सेवा सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) श्री अनुराग वर्मा ने भी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी।

खानपुर पुलिस को बीती रात मिली एक बड़ी सफलता

283.67 लीटर विदेशी शराब के साथ एक चार चक्का गाड़ी सहित एक शराब कारोबारी गिरफ्तार

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। खानपुर पुलिस को बीती रात मिली एक बड़ी सफलता। 283.67 लीटर विदेशी शराब के साथ एक टाटा पंच चार चक्का वाहन के साथ मौके पर एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफल रहा।वही बताते चले कि पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष शिवपूजन कुमार को दुरभाष के माध्यम से सूचना मिला कि समस्तीपुर बहेरी मुख्य पथ से खानपुर बाजार जाने वाली पक्की सड़क से एक चार चक्का वाहन पर विदेशी शराब ले जाने की सूचना मिला।

सूचना मिलते ही त्वरित कारवाई करते हुए उन्होंने पुलिस टीम में सबइंस्पेक्टर अजय कुमार दुबे, सबइंस्पेक्टर संजीवन कुमार, सबइंस्पेक्टर पूनम कुमारी के साथ शराब कारोबारी के मनसूबे पर पानी फेरते हुये पुलिस फोर्स के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर चौक के समीप एक टाटा पंच चार चक्का वाहन को रोक कर तलासी की गई। तलासी के क्रम में

थानाध्यक्ष शिवपूजन कुमार ने गिरफ्तार शराब कारोबारी को भेजा जेल

उक्त गाड़ी पर कार्टून में लोड विदेशी शराब बरामद किया गया। तथा मौके पर एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब व चार चक्का वाहन को जप्त करते हुए मौके पर गिरफ्तार शराब कारोबारी को थाना लाया गया। बरामद विदेशी शराब की कुल मात्रा 283.67 लीटर हुआ।

वही पूछताछ के क्रम में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम पप्पू कुमार उम्र करीब 26 वर्ष पिता सुधीर महतो-ग्राम सतमलपुर-थाना वारिसनगर के रूप में पहचान किया गया है। वही शराब के साथ गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष शिवपूजन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिला कि समस्तीपुर बहेरी मुख्य पथ से खानपुर बाजार की ओर एक चार चक्का गाड़ी पर विदेशी शराब लेकर आ रहा है।

सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए रंजीतपुर चौक के समीप एक चार चक्का वाहन को रोक कर तलासी के क्रम में उक्त गाड़ी पर विदेशी शराब लोड था। गाड़ी को जप्त करते हुये एक शराब कारोबारी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।वही चार चक्का गाड़ी पर लोड 283.67 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया।

वही पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष शिवपूजन कुमार ने शराब व चार चक्का गाड़ी को जप्त करते हुये गिरफ्तार शराब कारोबार पप्पू कुमार पिता सुधीर महतो ग्राम-सतमलपुर-थाना वारिसनगर के विरूद्व उत्पाद एवं मद्य निषेद्य अधिनियम 2018 के तहत थाना कांड संख्या-24/2026-धारा-30(a)/ के तहत प्राथमिकी दर्ज कर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं चौकीदार के साथ उचित अभिरक्षा में सरकारी वाहन से उपस्थापन हेतु माननीय न्यायालय समस्तीपुर भेजा गया है।

सुरक्षित सड़कों के साथ-साथ लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि सुरक्षित सड़कों के साथ-साथ लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए।

ये विचार उन्होंने आज यहां महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वर्कशॉप के उद्घाटन भाषण के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, लेकिन इससे सड़क हादसों की संभावना भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी सड़कों पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई बार लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट को सिर पर पहनने की बजाय हाथ या हैंडल पर लटका लेते हैं और जब हादसा हो जाता है तो इस गलती का उन्हें गंभीर नतीजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशा करके वाहन चलाने से जहां लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं, वहीं निर्दोष राहगीरों को भी खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने एन.एच.ए.आई. और लीड एजेंसी को ब्लैक स्पॉटों को समाप्त करने के लिए अधिक तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरूआत करके कीमती जानों को बचाने का एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके कारण पंजाब राज्य में हादसों में मरने वालों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई हादसा हो जाए तो हादसा पीड़ितों की मदद अवश्य करें, क्योंकि जितनी जल्दी हादसा पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उतनी ही उस व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ जाती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) आधुनिक सड़क सुरक्षा अभ्यासों को अपनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध डिजाइन, नियमित रख-रखाव और सुरक्षित इंजीनियरिंग मानक हादसों को कम करने तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वर्कशॉप के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने एक सुरक्षित प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित सड़क डिजाइन, प्रभावी प्रवर्तन और निरंतर जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के परिणाम सुरक्षित इंजीनियरिंग, नियंत्रित गति, सुरक्षित वाहनों और हादसे के बाद फौरी प्रतिक्रिया के संयोजन पर निर्भर करते हैं।

मनरेगा बचाओ अभियान के तहत 5 फरवरी को करनाल में धरना प्रदर्शन: राजबीर शर्मा

संजना भारती संवाददाता

असन्ध। मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 5 फरवरी को जिला सचिवालय के सामने करनाल में मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ग्रामीण डॉ. राजेश वैद्य के नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश गुप्ता की अध्यक्षता में धरना दिया जाएगा और रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उपरोक्त विचार कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन महासचिव ग्रामीण राजबीर शर्मा अरडाना ने कहे। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाग लेगें। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की रीढ़ है और करोड़ों गरीब परिवारों के सम्मान से जीने का अधिकार है। भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर कर धीरे-धीरे समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई मनरेगा योजना करोड़ों गरीबों, किसानों और मजदूरों की आजीविका का आधार रही है।कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की मजदूरों और गरीबों के खिलाफ की जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हक की लड़ाई सड़क से संसद तक मजबूती से लड़ेंगी।

प्रभास ने की राशा थडानी की तारीफ

अभिनेत्री राशा थडानी ने फिल्म लईकी लईका के गाने छाप तिलक से गायन की शुरुआत की है। फिल्म द राजा साब के स्टार प्रभास ने राशा के गायन प्रतिभा की खूब सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी है।

प्रभास ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में राशा थडानी का गाना छाप तिलक शेयर किया और लिखा, वाह, शानदार शुरुआत राशा थडानी। तुम्हारा प्रदर्शन सच्चा, भावपूर्ण और दिल से निकला हुआ है। बधाई हो। राशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रभास का आभार जताते हुए लिखा, प्रभास सर, मैं हमेशा आभारी रहूंगी।

फिल्म लईकी लईका एक आने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें राशा मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ अभय वर्मा हैं। फिल्म की पहली झलक में स्ट्रीट स्टाइल और आधुनिक ग्रैफिटी का मिश्रण दिखता है। पहले पोस्टर में अभय और राशा एक संकरी, धुंधली गली में एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए। अभय ने गहरे रंग की टेक्सचर्ड जैकेट पहनी है, जो फटी हुई है। राशा ने हल्के रंग की पारंपरिक कुर्ती पहनी है, जिस पर खून के छींटे लगे हुए हैं। यह एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का लेखन और निर्देशन सौरभ गुप्ता ने किया है। सह-निर्माता भावना दत्ता तलवार और राघव गुप्ता हैं। राशा और अभय की फिल्म लईकी लईका 2026 की गर्मियों में रिलीज हो सकती है।

मेधा राणा ने बताया कैसा रहा बॉर्डर-2 की शूटिंग का अनुभव

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर-2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म में लीड रोल्स की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन फिल्म में मेधा राणा ने भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। मेधा ने मेजर होशियार सिंह दहिया की पत्नी धनवंती देवी का रोल प्ले किया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री खुद एक आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वे उस डर और इमोशंस को जी चुकी हैं, जिन्हें फिल्म में दिखाया गया है। बॉर्डर-2 जैसी फिल्म में सेलेक्ट होने के अनुभव पर मेधा राणा ने आईएएनएस से कहा, जब मुझे पहली बार कॉल आया तो मैं खुशी से रो पड़ी थी। फिल्म के लिए मैंने कई राउंड ऑडिशन दिए थे और कास्टिंग डायरेक्टर छाबड़ा सर ने मुझे बुलाकर सामने से बताया था कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूं। वो पल मेरे लिए सबसे प्यारा था और खुशी के मारे मैं बहुत रोई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अब काम करने के बाद खुद पर धीरे-धीरे यकीन कर पा रही हूं।

फिल्म में मेधा ने मेजर होशियार सिंह दहिया की पत्नी धनवंती देवी का किरदार निभाया है। अपने किरदार पर बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, ये किरदार इमोशनली बहुत स्ट्रांग था क्योंकि ये उन पत्नियों की हिम्मत को दिखाता है, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई तो मैं समझ गई कि किरदार बहुत सारी जिम्मेदारी और इमोशंस के साथ आता है। अभिनेत्री ने आगे कहा, मेरे परिवार की तीन पीढ़ियों ने आर्मी में सेवा दी है और मेरे पापा आज भी सेवाएं दे रहे हैं और यही कारण है कि इस फिल्म को पूरी जिम्मेदारी से निभाना मेरा फर्ज था। हमने भी उन इमोशंस को जिया है, जो फिल्म में पर्दे पर दिखाए गए हैं।

बॉर्डर-2 में बॉर्डर से अलग क्या देखने को मिलेगा के सवाल पर मेधा ने बताया कि हर फिल्म का किरदार अलग है और इमोशन और हिम्मत से भरा है। फिल्म में प्यार, इमोशन, फैमिली, और हिम्मत को दिखाया गया है क्योंकि नहीं पता कि वापस कब लौट पाएंगे। चारों किरदार अलग हैं, लेकिन चारों कहानी ही पूरी फिल्म को बनाती हैं।

फिल्म को लेकर खुद को तैयार करने के सवाल पर मेधा ने बताया कि जो मेरा किरदार है, वो मेरी नानी पहले जी चुकी हैं, क्योंकि 1971 के समय मेरी मां का जन्म हुआ था और नाना की पोस्टिंग बांग्लादेश में थी। मेरी नानी ने मुझे बहुत सारी कहानियां और टिप्स भी दीं, जिससे मुझे फिल्म के किरदार को निभाने में बहुत मदद मिली। वरुण धवन के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर मेधा ने कहा, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया और शूटिंग के समय काफी कुछ सीखने को मिला। सेट पर पहला दिन काफी नर्वसनेस के साथ बीता था, लेकिन वरुण ने काफी मदद की।

ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 के निर्देशन को लेकर लिखी खास बात

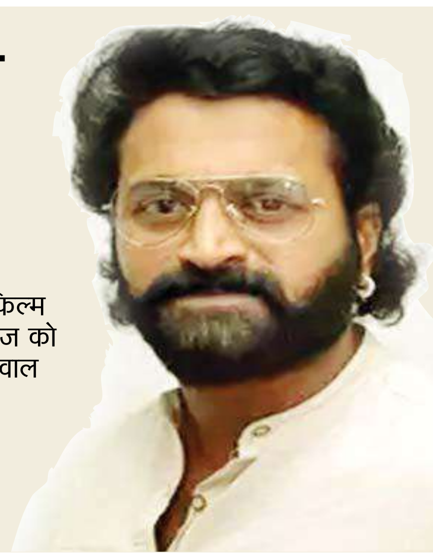

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 पिछले साल 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था।

वहीं ऋषभ ने कांतारा चैप्टर 1 की कई बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं और साथ ही एक खास नोट भी लिखा है। ऋषभ शेट्टी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर कांतारा चैप्टर 1 की सेट से कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन सभी तस्वीरों में वह आस-पास के लोगों को सीन समझाते नजर आ रहे हैं।

इस पोस्ट के साथ ऋषभ ने कैप्शन में लिखा, अपने किरदारों को जीवंत बनाना निर्देशन का सबसे अच्छा हिस्सा है। इसके साथ ही ऋषभ ने आगे लिखा, एक नया कर्ज लेना ठीक है। फैंस ने कमेंट कर लिखा है कि ऋषभ को ऑस्कर मिलना चाहिए। वहीं कई फैंस ने उनकी अगली फिल्म की रिलीज को लेकर सवाल किए हैं।

पारुल गुलाटी ने फिल्म 'तू या मैं' में अपनी भूमिका को लेकर की बात

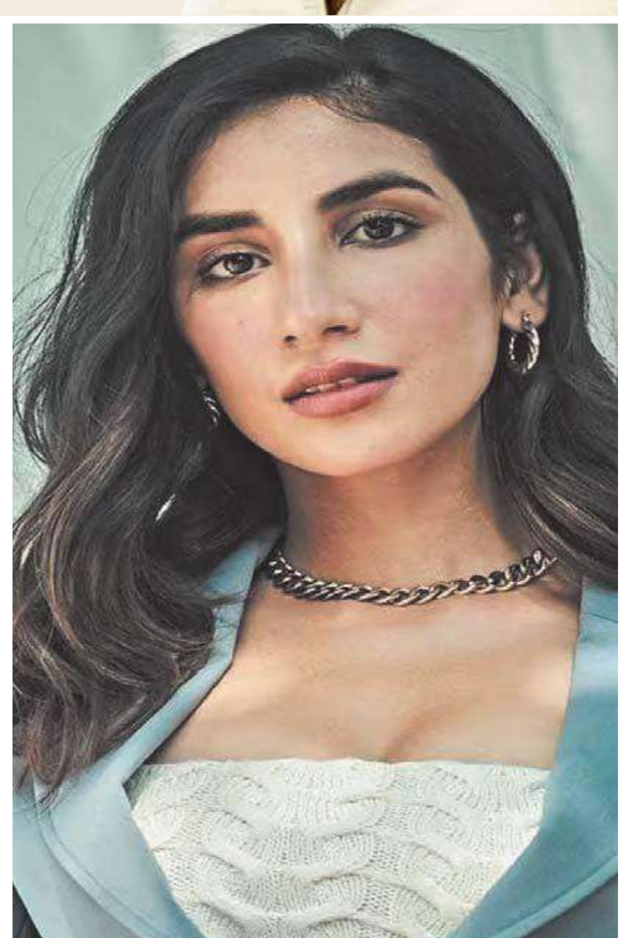

अभिनेत्री पारुल गुलाटी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'तू या मैं' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है। अब फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री पारुल गुलाटी ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात की।

तू या मैं में पारुल गुलाटी शनाया कपूर की करीबी दोस्त और मैनेजर लैरा का किरदार निभा रही हैं। अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए पारुल ने कहा कि मैं सचमुच बहुत खुश हूं और ईमानदारी से कहूं तो अभी भी इस किरदार को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही हूं। लैरा शनाया की दोस्त और मैनेजर है, जो मजबूती से उसका साथ देती है। उससे सवाल करती है, उसका समर्थन करती है और बहुत ही वास्तविक है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वह सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं है। वह कहानी में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक कड़ी है और इतने यादगार संवाद का हिस्सा बनना पहले से ही अविश्वसनीय लग रहा है।

अभिनेत्री ने आगे बताया कि एक अभिनेत्री और एक निर्माता के तौर पर यह मेरे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन कोलैबरेशन है। आनंद एल राय की दुनिया इतनी नाटकीय, बहुआयामी और भावनात्मक रूप से समृद्ध है, यह उस तरह का सिनेमा है जिसकी मैं हमेशा से प्रशंसक रही हूं और जिसका हिस्सा बनना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि यह एक बड़े पर्दे की भव्य और दिल को छू लेने वाली फिल्म का हिस्सा बनने का एक दुर्लभ, जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर जैसा लगता है। बेजॉय नाम्बियार द्वारा निर्देशित तू या मैं का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने मिलकर किया है। फिल्म में आदर्श गौरव और शनाया कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 13 फरवरी को वेलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी।

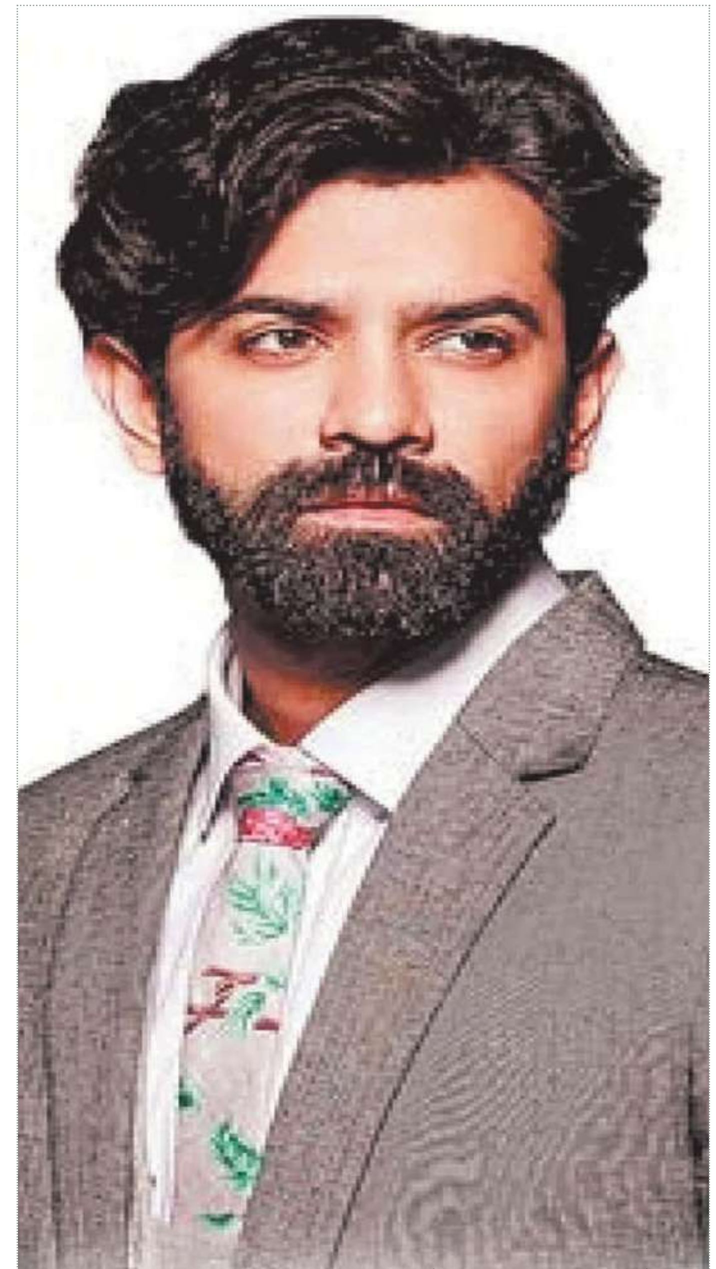

कोहरा 2 में अपने किरदार को लेकर बोले बरुन सोबती

दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली वेब सीरीज कोहरा का दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। पहली सीरीज की कहानी, रहस्य और रहस्यमयी वातावरण दर्शकों को इतना पसंद आया कि इसके दूसरे सीजन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।

इस बार की कहानी में रहस्य और मामले पहले से भी ज्यादा जटिल होंगे। इस बार भी अभिनेता बरुन सोबती अपने पहले वाले किरदार अमरपाल गारुडी के रूप में नजर आएंगे। सीरीज में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बरुन ने कहा, इस सीजन में गारुडी पहले से ज्यादा सतर्क है। वह हर कदम पर सोच-विचार करता है और अपने फैसलों और विकल्पों का लगातार मूल्यांकन करता है। गारुडी इस बार नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहता है, लेकिन कोहरा की दुनिया में बीते समय और पुराने अनुभव उसे पीछे नहीं छोड़ते। रहस्य इस बार और गहरा है और केस की जटिलता उसकी मानसिक स्थिति और फैसलों में भी दिखती है। बरुन ने कहा, इस सीजन ने मुझे अभिनेता के रूप में नई चुनौतियां दी हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस कहानी में गहराई से जुड़ेंगे। कोहरा 2 की कहानी इस बार जगराना से आगे बढ़ते हुए दलेरपुरा पहुंचती है, जहां माहौल पहले से ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी है। एएसआई अमरपाल गारुडी का तबादला दलेरपुरा पुलिस स्टेशन में हो जाता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है।

इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण मोना सिंह हैं, जो गारुडी की नई कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर की भूमिका निभा रही हैं। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, सोच अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सच तक पहुंचना। जैसे-जैसे वे एक हत्या के मामले की परतें खोलते हैं, वैसे-वैसे उनके अपने अतीत से जुड़े कई दबे हुए राज भी सामने आने लगते हैं। पंजाब की पृष्ठभूमि में बुनी गई यह कहानी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन हर मोड़ पर असर छोड़ती है। यह सीजन 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

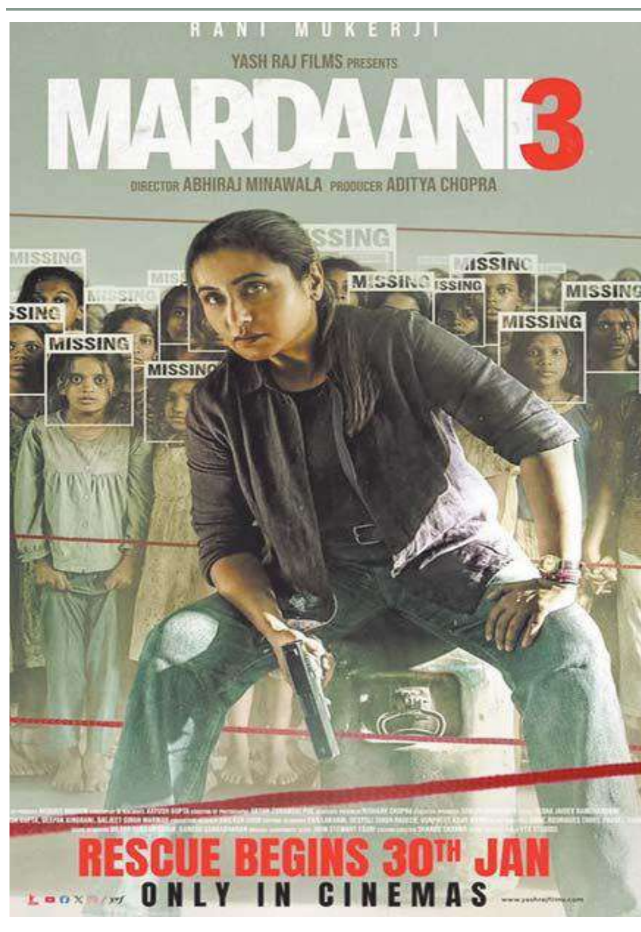

मर्दानी से थप्पड़ तक - बदली हीरोइन की परिभाषा बॉलीवुड ने महिलाओं की आवाज को बनाया ताकत

भारत में बेटियों के प्रति सामाजिक सोच बदलने और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को गुरुवार को 11 साल पूरे हो गए हैं। बॉलीवुड ने महिला केंद्रित कहानियों के जरिए समाज को प्रेरित करने का काम किया। 2014 के बाद रिलीज हुई कई फिल्मों ने यह संदेश दिया कि महिलाएं न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं, बल्कि अपने निर्णयों से समाज में बदलाव भी ला सकती हैं।

मर्दानी - रानी मुखर्जी की मर्दानी फैंचाइजी लोगों की पसंदीदा है। अब इस फैंचाइजी का तीसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। इसमें रानी ने शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया। 2014 में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी में शिवानी एक निडर पुलिस अधिकारी हैं, जो महिला उत्पीड़न और अपराध के खिलाफ लड़ती हैं। गोपी पुथरान के निर्देशन में बनी यह क्राइम थ्रिलर फिल्म पुरुष प्रधान मानसिकता के खिलाफ लड़ती है। रानी मुखर्जी ने अपने किरदार में भाव, चाल और फेमिनिस्ट रवैये के साथ पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर उठाया, जबकि विशाल जेठवा ने विलन के रूप में सस्पेंस और डर का असर बढ़ाया।

थप्पड़ - अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक दबाव की उन कहानियों को पर्दे पर उतारा, जिनमें अक्सर महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी नहीं हो पातीं। 2020 में रिलीज हुई फिल्म में तापसी पन्नू ने अमृता के किरदार में एक सामान्य गृहिणी के रूप में दिखाया कि कैसे एक छोटे से थप्पड़ ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। फिल्म में कई औरतों के जीवन की कहानियों को दिखाया गया, जिसके जरिए समझाया गया कि हर महिला अपने अधिकार के प्रति संवेदनशील होती है।

हिचकी - 2018 में रिलीज हुई फिल्म हिचकी में रानी मुखर्जी ने एक अलग ही भूमिका निभाई। फिल्म में वह टीचर नैना माथुर के किरदार में टॉरेट सिंड्रोम जैसी चुनौती का सामना करती हैं। 18 स्कूलों से रिजेक्ट होने के बावजूद नैना अपने सपनों को पूरा करने और बच्चों को पढ़ाने के अपने जुनून में लगी रहती हैं। सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी ड्रामा समाज में उन बीमारियों और मानसिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाती है, जिन्हें अक्सर हल्के में लिया जाता है। रानी का किरदार बताता है कि आत्मविश्वास और धैर्य से हर महिला अपने सपनों को सच कर सकती है।

डियर जिंदगी - 2016 में रिलीज हुई फिल्म में आलिया भट्ट और शाहरुख खान ने ऐसी कहानी प्रस्तुत की, जो मानसिक स्वास्थ्य और खुद को समझने के महत्व पर आधारित है। आलिया का किरदार कायरा अपनी जिंदगी की उलझनों और डर से जूझती है और मनोचिकित्सक शाहरुख खान उसे खुद को समझने और खुश रहने का तरीका सिखाते हैं। गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी यह फिल्म महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के संदेश को बखूबी पेश करती है।

राजी - फिल्म राजी में आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय देश की खातिर पाकिस्तान में जासूस बन जाती है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया। यह थ्रिलर न केवल देशभक्ति की कहानी बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि महिलाएं अपने साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सफल हो सकती हैं।

द केरल स्टोरी- निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी फातिमा उर्फ शालिनी (अदा शर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी सहेलियों गीतांजलि (सिद्धि इदनानी), निमाह (योगिता बिहानी) और आसिफा (सोनिया बलानी) के साथ नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती है, लेकिन इस दौरान वे कट्टरपंथी संगठनों के जाल में फंस जाती हैं। अदा शर्मा का किरदार डर, पीड़ा और बेचैनी के बावजूद अपनी पहचान और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूती से दिखाता है।